



अजिंक्य रहाणे ने ...

@ ਪੇਜ਼ 7

संक्षिप्त समाचार

## परवान घढ़ी भारत और अरब की दोस्ती

नई दिल्ली (एजेंसी)। अब देश विश्व के उन क्षेत्रों में शामिल हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है इन देशों में गणनीय व्यवस्था और विकास के बीच जटिल संबंध हैं विकास की गणनीति यहां कई सामाजिक, आर्थिक और भू-रजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है। अब देशों की अधिकांश सरकारों ने राजशाही शासनों पर आधारित हैं। सउदी अरब, कुवैत, कतर जैसे देशों में आज भी शाही परिवर्षों का शासन है लेकिन बहुत कठ बदलता हुआ भी नजदीक आ रहा है। अब देशों के यथा दुनियादारी को नए



नरसिंह से देख रहे हैं। अपने देश को दुनिया के साथ लेकर चल रहे हैं। एजेंड में मार्डानाइजेशन और संस्कृति दोनों शामिल हैं। नया अख आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उर्डु के प्रिस शेख खालिद और सऊदी अरब के प्रिस सलमान जैसे युवा नेता विश्व के पटल पर अपनी पहचान से दुनिया का परिचय करता रहे हैं। 42 साल के शेख हमदान, 43 साल के शेख खालिद और 39 साल के प्रिस सलमान अरब देशों की उम नई पीढ़ी को आगे ले जा रहे हैं जो आशुष्टिका के साथ-साथ बदलाव को अपना रही है। नई सोच पुणी रुद्धियों को चूनाती दे रही है। मजहब को कटूता से दुश्ग वो रहा है और बदलते ही वैशिक हालात में अख भी बदल रहा है। हाल के वर्षों पर नजर ढालें तो अख देखों ने विविधता को अपनाया है। पर्यटन, तकनीक, हरित ऊजा और शिक्षण के क्षेत्र में नए प्रयोग हो रहे हैं। जैसे सऊदी अरब की %विजन 2030% योजना, जिसका उद्देश्य तेत पर निर्भरता को कम करना और अर्थव्यवस्था को अलग दिशा देना है।

## दाक्षण कारया का सना न किम जोंग के सैनिकों पर

**चलाइ गोलिया**  
उत्तर कोरिया (एजेंसी)। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर से गहरा हो गया है। दक्षिण कोरिया के सैनिकों ने उत्तर कोरिया



के सैनिकों की ओर चेतावनी के तौर पर गोलियां दागी हैं। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों ने सीमा को पार किया था। इस कारण उसके सैनिकों ने उत्तर कोरिया के सैनिकों को चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाई हैं। हालांकि, इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर जाने की संभावना जारी ही है। एपी के मुताबिक, दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों के सीमा पार की थी। चेतावनी देने और गोलियां चलाने के बाद उत्तर कोरिया के लगभग 10 सैनिक अपनी सीमा में वापस लौट गए। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि वह उत्तर कोरिया की ओर से गतिविधियों पर कठी निगरानी रख रही है। उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा पर कई बार हिस्सक टकरावों की घटनाएं होती रही हैं। बीते साल जून महीने में भी उत्तर कोरियां सैनिकों ने सीमा का उल्लंघन किया था। इस बक्त भी दक्षिण कोरिया के सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थीं। इस बक्त दक्षिण कोरियां अधिकारियों ने इस बात का आकलन किया था कि उत्तर कोरियां सैनिकों ने जानबूझकर सीमा का उल्लंघन नहीं किया था। ये एक जगली इलाका था और वहां पर सैन्य सीमा रेखा साफ रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि, उत्तर कोरियां सैनिकों द्वारा मालवार को सीमा पार करने का कारण अब तक समझे नहीं आ पाया है।

## **सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिका, केंद्र ने भी दाखिल की कैविएट याचिका**



**नई दिल्ली (एजेंसी)।** वक्फ संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास करने के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है। अब वक्फ बिल कानून बन गया है। हालांकि, विपक्षी दल और मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के

**करने के बाद राष्ट्रपति से भी मंजूरी**

खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट आने वाले 16 अप्रैल की तारीख को वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई

A large green sign with white text is displayed in the foreground. The sign has two parts: the top part is in Urdu script reading "سیہ پار دلیش وقف" and the bottom part is in English capital letters reading "WAQF BOARD". In the background, a large assembly of people is seated in rows of blue chairs, facing towards the right side of the frame. The setting appears to be a formal conference or meeting room.

दूसरी ओर वक्फ कानून के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। कैविएट याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को सुने बिना बिना कोई भी एकत्रफा आदेश पारित नहीं किया जाए। अदालत कोई भी आदेश पारित करने से पहले केन्द्र सरकार की दलील भी सुने। इन लोगों ने दाखिल की याचिका: वक्फ कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 से अधिक याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। याचिका दाखिल करने वालों में - छख्य, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, दृष्टकूज जमीयत उलमा-ए-हिंद आदि शामिल हैं। बता दें कि याचिका के अन्तिम दृष्टिकोण में वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए विचार करने पर सहमति व्यक्त की जाएगी। याचिका के अन्तिम दृष्टिकोण में वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए विचार करने पर सहमति व्यक्त की जाएगी।



उप मुख्यमंत्री ने रीवा नगर में जल आपूर्ति व सीवरेज कार्यों की समीक्षा की

रीवा नगर "जीरो अनट्रीटेड वेस्ट" के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करे इसके लिए ठोस कार्ययोजना पर करें कार्य

**मीडिया ऑडीटर, रीवा**  
**(निप्र)**उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रीवा शहर तेज गति से प्रगति कर रहा है और विस्तारित हो रहा है। रीवा शहर में म्युनिसिपल वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में रीवा शहर "जीरो अनट्रीटेड वेस्ट" के लक्ष्य को प्राप्त करें, इसके लिए ठोस कार्योजना बनाकर क्रियान्वयन प्रारंभ करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जर्यती कुंज में स्थापित 12 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का संचालन शीघ्र प्रारंभ करने की दिशा में सभी आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएं। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय, भाषापाल में रीवा नगरीय क्षेत्र में संचालित सीवरेज, पेयजल आपूर्ति और अन्य विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

आवश्यक तकनीकी एवं  
प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध



ने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत रीवा नगर निगम क्षेत्र में संचालित पेयजल प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। प्रशासनिक सहयोग तत्काल रीवा को आवश्यक तकनीकी एवं

संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हों और उनकी गुणवत्ता से कोई सपन्होत्ता न किया जाए।

रीवा का स्मार्ट नगर के रूप में विकसित करने की दिशा में समन्वयित प्रयास करें: उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने रीवा क्षेत्र में पुनर्घटनाकारण कार्यों की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों से अद्यतन जानकारी प्राप्त कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि रीवा नगर को आधुनिक नगरीय सुविधाओं से युक्त स्मार्ट नगर के रूप में विकसित करने की दिशा में सभी विभाग समन्वयित प्रयास करें। अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय कुमार शुक्ला, आयुक्त नगरीय प्रशासन सिर्फी चक्रवर्ती, नगर निगम रीवा के आयुक्त सौरभ सोनवडे सहित नगरीय विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध हैं।

भारतीय सिंधू सभा ने पुष्पवर्षा  
कर शोभायात्रा का किया भव्य  
स्वागत वंदन अभिनंदन



मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। हिंदू पर्व समन्वय समिति के  
प्रत्याधान में श्री रामनवमी शोभा यात्रा के अवसर पर राष्ट्रीय समाजसेवी  
संस्था भारतीय सिंधु सभा सतना संस्थाध्यक्ष श्री अशोक चांदवानी के  
प्रत्युत्तम में श्री महावीर भवन के पास कमल सलेक्शन के सामने पुष्पवर्षा  
ने भव्य स्वागत- वंदन- अभिनंदन किया। संस्था के महामंत्री विनोद  
लालानी ने बताया शोभायात्रा का भव्य स्वागत करते हुए प्रभु श्रीराम का  
गाल्यार्पण के साथ पुष्पवर्षा करके आरती उतारी गयी।

स्वागत करने वालों में सीतीश सुखेजा विक्रम चौधरी गोपी गेलानी  
प्रीचंद मनवाणी गोपीचंद कापड़ी फेरमल तोलवानी राजलदास  
आडवाणी विजय जग्यासी मनोहर आरतानी विनोद गेलानी देवेंद्र  
नत्यवानी इंद्रलाल कापड़ी जेठानद वाधवानी पहलाजराय भावनानी  
परत कामदार नारायण दास गुलाबी गंगाराम सचदेव केशव मखीजा  
नंजय आहूजा पंकज आहूजा भानु हासवानी घनश्यामदास सोनी घनश्याम  
दास असर गुरुमुख पंजवानी महेश रावलानी संदीप तोलवानी मनोज  
गोतानी संजय नागदेव राजकुमार रोचलानी करतार कामरानी डॉ अशोक  
इलानी महेश रावलानी मर्नीष सदानी संजय वाधवानी शंकर सेनानी

**शोभायात्रा में आकर्षण का केंद्र  
रही रक्तदान की झाँकी**



**मीडिया अॉडीटर, सतना (निप्र)**। हिन्दू पर्व समन्वय समिति के गत्वाधान में श्री रामनवमी महोसुक्ष के अवसर पर निकली शोभायात्रा में समाजसेवी संस्था सिन्धु विकास समिति संस्थाध्यक्ष विनोद गेलानी के बानिध्य में रक्तदान जग्सकूला झांकी के साथ शामिल हुई

सर्वसमाज के युवाओं एवं मातृशक्ति को मानवता सेवार्थ रक्तदान का लिए प्रेरित कर रही स्मृथि विकास समिति की यह झांकी शोभायात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। संस्था मंत्री महेश रावलानी ने जानकारी देते हुए रक्तताया रक्तदान की मौखिक जानकारी के साथ रक्तदान विषयात्थ पंपलेट वितरण भी किया गया। झांकी सजाने में ज्ञान खटवानी, दिलीप तोनी, संजय वाधवानी, बंसी नागदेव, मनीष सदानी का उल्लेखनीय प्रोग्राम रहा। शोभायात्रा में संस्था के संरक्षक श्रीचंद मनवाणी गोपी लानी मनोहर डिग्वानी अध्यक्ष विनोद गेलानी अशोक चांदवानी वनश्याम मंधरानी गोपीचंद कापड़ी मनोहर लाल वाधवानी जेठानंद वाधवानी संजय वाधवानी गंगाराम सचदेव दिलीप सोनी अमित घोघवानी रुफल पुरस्वानी दीपक वाधवानी मनीष सदानी बंसी नागदेव मनोहर आरतानी मनमोह माहेश्वरी विभाष बनर्जी आकाश बनर्जी अनिल तोटवानी इंद्रलाल कापड़ी अशोक भामानी गुरुमुख पंजवानी रूपेश वालेचा विशेषाल राजपाल कैलाश वाधवानी महिला मंडल से रखी होतचंदानी सेमरन होतचंदानी मोना चोपड़ा डॉक्टर मनीषा सोई आभा सिंह प्रमुख व्य से शामिल रहे।

**सदस्यता सूची के संबंध में दावे-आपत्ति 15 अप्रैल तक**

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण सहकारी समिति मयर्सिट नर्वी बटालियन विशेष सशस्त्र बल रीवा के नंचालक मण्डल के सदस्यों का चुनाव किया जाना है। इस संबंध में जिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि संचालक मण्डल के सदस्यों के चुनाव के लिए समिति की सदस्यता सूची 7 अप्रैल को प्रकाशित कर दी रही है। सूची का प्रकाशन उप पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय, जनपद नंचायत रीवा कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कार्यालय तथा समिति के सूचना पटल पर कर दिया गया है। सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियाँ 15 अप्रैल तक समिति कार्यालय में लिखित में प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 16 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से समिति कार्यालय में किया जाएगा। आपत्तियों के निराकरण के बाद सदस्यता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा।

**द्वंधटना में पीडित परिजनों को देंगे लाभ**

**मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)**। कलेक्टर प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में अजात वाहन से सड़क दुर्घटना में धायल/मृतक के निकटतम वारिसों को हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना में पीड़ित परिजनों को लाभ दिलाये जाने के संबंध में बैठक 9 अप्रैल को आयोजित की गई है। कलेक्टर के बोहन सभागार में अपाराह्न 4 बजे से आयोजित बैठक में संबंधितों को

**करार आरोपी पर ईनाम घोषित किया**

मीडिया ऑडीटर, गीवा (निप्र)। पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश सेहं चर्देल ने फरार आरोपी देवमुनि माझी पिता मैकू प्रसाद उम्र 60 वर्ष सेहं नेवासी जेल रोड ट्यॉथर की दस्तयाबी/गिरफ्तारी पर बीस हजार रुपये के ईनाम की घोषणा की है। इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा उक्त करार आरोपी पर दस हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था जिसे पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा आरोपी की दस्तयाबी, गिरफ्तारी, पतासाजी करने या कंसी प्रकार की सहायता करने या सूचना देने पर बीस हजार रुपये की गंद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।

**जेला योजना समिति की बैठक 17 को**

मीडिया ऑडीटर, गीवा (निप्र)। जिला योजना समिति की बैठक 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे से कलेक्टरेट के मोहन सभागार में आयोजित की गई है। बैठक की शाखाएँ निम्न तथा पांचांग तारीख पांचांग पार्श्व पार्श्व

इ हा बठक का अध्यक्षता जिल के प्रभारा मत्रा तथा पचायत एवं ग्रामवेकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री आवेदन के बारे में विवाद हो सकता है।

गोजना, प्रधानमंत्री जनमन सङ्क योजना, पेयजल, जल गंगा संवर्धन अभियान सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने समिति के सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को विश्वभागीय योजनाओं की अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

## विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हुई संगोष्ठी

**मीडिया ऑडीटर, गीवा (निप्र)।** जन शिक्षण संस्थान द्वारा गत देवस विश्वकर्ण केन्द्र कुठुलिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वन्दना तिवारी ने कहा कि मनुष्य अपना तथा समाज का विकास अभी कर सकते हैं, जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हों।

# विद्या

## भारत का महा आर्थिक संकट, शेयर बाजार और बैंकों में हाहाकार

भारत में आर्थिक मंदी जिस तरह से सामने आ रही है। जिसमें अर्थतंत्र के सारे संस्थान डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर बाजार में पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट को थामने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने लाखों करोड़ रुपया शेयर बाजार में डाला। वह रुपया भी मुनाफा वसूली में शेयर बाजार से बाहर निकल गया। रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में डिविडेंड के नाम पर काफी बड़ी राशि वसूल कर की है। जिसके कारण रिजर्व बैंक का आर्थिक संकट भी सामने दिख रहा है। रही सही कसर सरकारी बैंक पूरी कर रहे हैं। बैंकों द्वारा जो फाइनेंस किया गया है। उसकी वसूली नहीं हो पा रही है। बैंकों द्वारा पिछले वर्षों में खातेदारों से तरह-तरह के शुल्क लगाकर अनाप-शनाप वसूली की जा रही है। एनपीए खाते की रकम का समयोजन कर बैंकों का मुनाफा बैलेंस शीट में लाभ से एडजस्ट किया जा रहा है। पिछले वर्षों में शेयर बाजार में बैंकों द्वारा भारी निवेश किया गया है। जब तक शेयर बाजार में तेजी बनी हुई थी। तब तक बैंकों की बैलेंस शीट मुनाफा उगल रही थी। अब बैंकों की बैलेंस शीट घाटे की ओर आगे बढ़ रही हैं। जीवन बीमा निगम जैसी कंपनियां लड़खड़ा रही हैं। म्युचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थान भी शेयर बाजार की गिरावट के कारण आर्थिक हालत खराब होती चली जा रही है। भारत के करोड़ों परिवार कर्ज के जाल में फँसे हुए हैं ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है। उसके अनुसार 68 फीसदी कर्जदारों को ईएमआई चुकाने में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। 45 अरब डॉलर का कर्ज फँसा हुआ है। 91 से 180 दिनों के भीतर लोन की किस्त जमा नहीं होने पर बैंक यह राशि एनपीए में डाल देते हैं। एनपीए 3.3 फीसदी की रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है। 2023 में यह आंकड़ा मात्र 0.8 फीसदी था। भारत में लोन चुकाने के लिए अब लोग लोन ले रहे हैं। आर्थिक संकट के कारण लोगों को अपने बच्चों को स्कूलों से बाहर निकालना पड़ रहा है। बैंकों में लोन डिफाल्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रिजर्व बैंक के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस के तहत बड़ी मात्रा में पर्सनल ऋण दिया गया है। इस ऋण की भी वसूली नहीं हो पा रही है। 10 में से 9 लोगों के पास औपचारिक और स्थाई नौकरी नहीं है। जिसके कारण वह लोन की किस्त नहीं चुका पा रहे हैं। समूह लोन जो दिया गया था, वह भी वसूल नहीं हो पा रहा है। माइक्रो फाइनेंस के लोन की किस्तें भी लोग नहीं चुका पा रहे हैं। लोगों के पास पर्यास आय नहीं है, उनकी मासिक खर्च लायक आमदनी नहीं हैं।

# टैरिफ युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं होगा अधिक प्रभाव

दिनांक 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डॉनल्ड ट्रप द्वारा, विभिन्न देशों से अमेरिका में होने वाले आयातित उत्पादों पर की गई टैरिफ सबंधी घोषणा के साथ ही अंततः अमेरिका द्वारा पूरे विश्व में टैरिफ के माध्यम से व्यापार युद्ध छेड़ दिया गया है। अभी, अमेरिका ने विभिन्न देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर विभिन्न दरों पर टैरिफ लगाया है। अब इनमें से कई देश अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहे हैं, जैसे चीन ने अमेरिका से चीन में आयात होने वाले उत्पादों पर दिनांक 10 अप्रैल 2025 से 34 प्रतिशत की दर से टैरिफ लगाने की घोषणा की है। टैरिफ के माध्यम से छेड़ गए व्यापार युद्ध का भारत पर कोई बहुत अधिक विपरीत प्रभाव पड़ने की समावना कम ही है। दरअसल, अमेरिका ने विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों पर अलग अलग दर से टैरिफ लगाने की घोषणा की है और साथ ही कुछ उत्पादों के आयात पर फिलहाल टैरिफ की नई दरें लागू नहीं की गई हैं। टैरिफ की यह दरें 9 अप्रैल 2025 से लागू होंगी।

**गई हैं। टैरिफ की यह दरें 9 अप्रैल 2025 से लागू होंगी।**



विभिन्न देशों से अमेरिका में आयात होने वाले उत्पादों पर 10 प्रतिशत की दर से न्यूनतम टैरिफ लगाया गया है। साथ ही, कुछ अन्य देशों यथा चीन से आयातित उत्पादों पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है। इसी प्रकार, वियतनाम से आयातित उत्पादों पर 46 प्रतिशत, ताईवान पर 32 प्रतिशत, थाईलैंड पर 36 प्रतिशत, भारत पर 26 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत, इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत, स्विटजरलैंड पर 31 प्रतिशत, मलेशिया पर 24 प्रतिशत, कम्बोडिया पर 49 प्रतिशत, दक्षिणी अफ्रीका पर 30 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 37 प्रतिशत, पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत, श्रीलंका पर 44 प्रतिशत और इसी प्रकार अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर भी अलग अलग दरों से टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है। कुछ उत्पादों जैसे, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो, ताम्बा, फार्मा उत्पाद, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, बुलीयन एवं अन्य महत्वपूर्ण मिनरल्स को अमेरिका में आयात पर टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। अमेरिका का मानना है कि वैश्विक स्तर पर अन्य देश अमेरिका में उत्पादित वस्तुओं के आयात पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका में इन देशों से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर अमेरिका द्वारा बहुत कम दर पर टैरिफ लगाया जाता है अथवा बिलकुल नहीं लगाया जाता है। जिससे, अमेरिका से इन देशों को नियांत कम हो रहे हैं एवं इन देशों से अमेरिका में आयात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार, अमेरिका का व्यापार घाटा असहनीय स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ साथ, अमेरिका में विनिर्माण इकाईयां बंद होकर अन्य देशों में स्थापित हो गई हैं और इससे अमेरिका में रोजगार के नए अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे हैं।

का हब बनाने के उद्देश्य से अमेरिका को पुनः महान बनाने का आङ्हान किया है और इसी संदर्भ में विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि अमेरिका में आयातित उत्पाद महंगे हों और अमेरिकी नागरिक अमेरिका में ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने की ओर प्रेरित हों। वर्तमान में बढ़े हुए टैरिफ का बोझ अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उहें अमेरिका में महंगे उत्पाद खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाय नहीं जा सकता अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की अमेरिका में स्थापना हो एवं इन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को महंगे उत्पाद खरीदने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। इससे अमेरिका में एक बार पुनः मुद्रा स्फीति की समस्या उत्पन्न हो सकती है एवं ब्याज दरों के कम होने के चक्र में भी देरी होगी, बहुत सम्भव है कि मुद्रा स्फीति को कम करने की दृष्टि से एक बार पुनः कहीं ब्याज दरों के बढ़ने का चक्र प्रारम्भ न हो जाए। लम्बे समय में जब अमेरिका में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो जाएगी एवं इन इकाईयों में उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा तब जाकर कहीं मुद्रा स्फीति पर अंकश लगाया जा सकेगा। विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों पर टैरिफ सम्बंधी घोषणा के साथ ही, डॉलर पर दबाव पड़ना शुरू भी हो चुका है एवं अमेरिकी डॉलर इंडेक्स घटकर 102 के स्तर पर नीचे आ गया है जो कुछ समय पूर्व तक लगभग 106 के स्तर पर आ गया था। इसी प्रकार अमेरिका में सरकारी प्रतिभूतियों की 10 वर्ष की बांड यील्ड पर भी दबाव दिखाई दे रही है और यह घटकर 4.08 के स्तर पर नीचे आ गई है, यह कुछ समय पूर्व तक 4.70 के स्तर से भी ऊपर निकल गई थी।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रूपए की कीमत 1 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़नी प्रारम्भ हो गई है एवं यह पिछले चार माह के उच्चतम स्तर, लगभग 85 रूपए प्रति अमेरिकी डॉलर, पर आ गई है। ट्रम्प प्रशासन के टैरिफ सम्बंधी लिए गए निर्णयों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर लम्बी अवधि में तो हो सकता है परंतु छोटी अवधि में तो निश्चित ही यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहा है। अमेरिकी पूंजी बाजार (शेयर बाजार) केवल दो दिनों में ही लगभग 10 प्रतिशत तक नीचे गिर गया है और अमेरिकी निवेशकों को लगभग 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। इतनी भारी गिरावट तो वर्ष 2020 में कोविड महामारी के दौरान ही देखने को मिली थी। यदि यही स्थिति बनी रही तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था कहीं मंदी की चेपट में न आ जाय। यदि ऐसा होता है तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी विपरीत रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। अतः ट्रम्प प्रशासन का टैरिफ सम्बंधी उक्त निर्णय अति जोखिम भरा ही कहा जाएगा।

जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी कुछ तो विपरीत असर होगा ही। इस संदर्भ में किए गए विश्लेषण से यह तथ्य उभरकर सामने आ रहा है कि बहुत सम्भव है कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए 26 प्रतिशत के टैरिफ़ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक विपरीत प्रभाव नहीं हो। क्योंकि, एक तो भारत से अमेरिका को निर्यात बहुत अधिक नहीं है। यह भारतीय सकल घेरेलू उत्पाद का मात्र लगभग 3-4 प्रतिशत ही है। वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर नहीं है एवं यह विभिन्न उत्पादों की अंतिरिक मांग पर अधिक निर्भर है। भारत से सकल घेरेलू उत्पाद का केवल लगभग 16 प्रतिशत (वस्तुएं एवं सेवा क्षेत्र मिलाकर) ही निर्यात किया जाता है। दूसरे, भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने कुछ उत्पादों को उक्त टैरिफ़ व्यवस्था से फिलहाल मुक्त रखा गया है, जैसे फार्मा उत्पाद, सेमीकंडक्टर, स्टील, अल्यूमिनियम, ऑटो, ताम्बा, बुलीयन, एनर्जी आदि। संभवतः इन उत्पादों के भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर कुछ भी असर नहीं होने जा रहा है। तीसरे, भारतीय कम्पनियों (26 प्रतिशत टैरिफ़) को रेडीमेड गार्मेंट्स के अमेरिका को निर्यात में पड़ोसी देशों, यथा, बांगलादेश (37 प्रतिशत टैरिफ़), पाकिस्तान (29 प्रतिशत टैरिफ़), श्रीलंका (44 प्रतिशत टैरिफ़), वियतनाम (46 प्रतिशत टैरिफ़), चीन (34 प्रतिशत टैरिफ़), इंडोनेशिया (32 प्रतिशत टैरिफ़), आदि के साथ अत्यधिक स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। परंतु, उक्त समस्त देशों से अमेरिका को होने वाले रेडीमेड गार्मेंट्स के निर्यात पर भारत की तुलना में अधिक टैरिफ़ लगाए जाने की घोषणा की गई है। अतः इन देशों से रेडीमेड गार्मेंट्स के अमेरिका को निर्यात भारत की तुलना में महंगे हो जाएंगे, इससे रेडीमेड गार्मेंट्स के क्षेत्र में भारत के लिए लाभ की स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कृषि उत्पादों के निर्यात भी भारत से अमेरिका को बढ़ सकते हैं। यदि किन्हीं क्षेत्रों में भारत को नुकसान होता हुआ दिखाई भी देता है तो भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ बहुत अच्छे राजनैतिक संबंधों के चलते भारत को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी, अमेरिका सहित भारत के यूरोपीयन देशों, ब्रिटेन एवं खाड़ी के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को सम्पन्न करने हेतु वार्ताएं लगभग अंतिम दौर में पहुंच गई हैं, इसका लाभ भी भारत को होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शीघ्र ही मोनेटरी पॉलिसी के माध्यम से रेपो दरों में परिवर्तन की घोषणा की जाने वाली है। भारत में चूंकि मुद्रा स्फीति की दर लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है अतः भारत में रेपो दर में 75 से 100 आधार बिंदुओं की कमी की घोषणा की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो विभिन्न उत्पादों की उत्पादन लागत में कुछ कमी सम्भव होगी, जिसके चलते भारत में निर्मित उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। हालांकि, केवल व्याज दरों के कमी करके पूँजी की लागत को कम करने से काम चलने वाला नहीं है, भारत को भूमि एवं श्रम की लागतों को भी कम करने की आवश्यकता है तथा उत्पादकता में सुधार करने की भी आवश्यकता है ताकि भारत में निर्मित होने वाले उत्पादों की कुल लागत में कमी हो एवं यह उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी में अन्य देशों के मुकाबले में टिक सकें।

## आरएसएस मुख्यालय में मोदी- क्या यह संघम शरण गछामि है?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाल में नागपुर-स्थित आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। वहाँ उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉ के बी। हेडगोवार और द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। इस यात्रा का खूब प्रचार हुआ और इसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का क्यास है कि चौंकि अगले सितम्बर में मोदी 75 साल के हो जाएंगे और अपनी पार्टी के नियमों के अनुसार उन्हें सक्रिय राजनीति से सन्यास लेना होगा, इसलिए यह उनकी फेयरवेल यात्रा शी। इस तीन कई

फरयरवल थीं याजा था! इस बाच कइ घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि पिता (आरएसएस) और बेटे (भाजपा) के रिश्तों में कुछ खटास आ गयी है। सन 2024 के आमचुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष जे पाए। नंदा ने कहा था कि भाजपा अब अपने पैरों पर खड़ी हो गयी है और उसे आरएसएस के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके पहले तक भाजपा इतनी मज़बूत नहीं थी इसलिए उसे बोट हासिल करने के लिए आरएसएस की मदद की दरकार रहती थी एक दूसरा मसला है मोदी का आसमान छूता अहंकार। उन्होंने कहा कि वे नॉन-बायोलॉजिकल हैं और ईश्वर ने उन्हें इस धरती पर अपना ढूत बनाकर भेजा है। संघ के मुख्या मोहन भागवत को लगा कि मोदी का अहं बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की कि कुछ लोग खुद को देवता और फिर भगवान मानने लगते हैं।



स्पष्ट श्रम विभाजन है।

इसका सबसे बाढ़या उदाहरण था 1980 के दशक में विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा शुरू किया गया राममंदिर आन्दोलन। भाजपा ने इस आन्दोलन को अपने हाथों में ले लिया और उसके ज़रिये जमकर वोट कबाड़े। आरएसएस लगातार प्राचीन भारत का महिमामंडन करता है और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमज़ोर वर्गों जैसे दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के बारे में गलत धारणाएं फैलाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी शाखाओं का विशाल जाल और लोगों से जुड़ने की उसकी कई

कार्यविधियाँ।

यद्यपि भारत का सामता और औपनिवेशिक समाज अब प्रजातान्त्रिक बन चुका है मगर आरएसएस अब भी अपनी शाखाओं के ज़रिये राजे-रजवाड़ों के दौर में व्यास जातिगत और लैंगिक ऊंचनीच और सामती मूल्यों को बढ़ावा देता है। उससे जुड़े एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती, राष्ट्रसेविका समिति आदि भी यही काम करते हैं।

समाज के विभिन्न तबकों और राजनैतिक ढांचे में घुसपैठ करने का काम आरएसएस बहुत लम्बे समय से कर रहा

है। मगर पहले राज्यों और अब केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने से इस प्रक्रिया में जबरदस्त तेजी आई है। अब संघ अपनी विचारधारा को और फैलाने के लिए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के समूह गठित कर रहा है। मैं मुंबई के जिस इलाके में रहता हूँ, वहां संघ ने हाल में एक पिकनिक का आयोजन किया। एक मुस्लिम महिला उसमें भाग लेना चाहती थी मगर उसे सीधे-सीधे कह दिया गया कि पिकनिक के दौरान जो बातें की जाएंगी उससे वो असहज महसूस करेगी। सुबह-सुबह हाथों में लाठियां लिए जाती महिलाओं को देखकर आप यह समझ

सकते हैं कि वे राष्ट्र सेविका समिति की शाखा में जा रहीं हैं।

पिछले एक दशक के भाजपा शासन में आरएसएस के अपने हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडा के कई लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। राममंदिर बन चुका है, अनुच्छेद 370 हटाया जा चुका है, मुहंजबानी तलाक गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। वक्फ के मामले में संसद में बहस चल रही है।

यह साफ़ है कि आरएसएस और भाजपा के बीच कोई विवाद या असहमति नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि दोनों के बीच हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति के

मामले में कुछ मतभेद हों।  
मोदी ने हेडोवार और गोलवलकर के तरीफ करते हुए कहा कि उन्होंने देश को सही राह दिखाई। वह राह क्या है? पहली तो यह कि आजादी, बराबरी और भाईचारे के मूल्यों को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाले भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलन से सुरक्षित दूरी बनाई रखी जाए। दूसरे बिना स्वीकार करे गोलवलकर के इस सिद्धांत का पालन किया जाए कि मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट हिन्दू राष्ट्र के दुश्मन हैं। इस साल (2025) की ईद-उल-फित्र इसका उदाहरण हैं। एक राज्य में उसे सार्वजनिक की बजाय ऐच्छिक छुट्टी घोषित कर दिया गया। सड़क पर नमाज अदा करने का विरोध किया जा रहा है।



## इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद, अलाहबादिया को नहीं मिलेगा पासपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। रणवीर ने अपने खिलाफ दर्ज अलग-अलग स्ट्रॉक्स के एक जगह क्लब करने की मांग की थी। इस पर जरिस सूखकांत और जस्टिस एन कोटिशर सिंह की बैच ने सुनवाई की। अलाहबादिया की तरफ से बैकील अभिनव चंद्रचूड़ कोर्ट में उनका पक्ष रखा। चंद्रचूड़ ने कोर्ट से उनका पासपोर्ट जमा करने से जुड़ी शर्त में छूट देने की मांग की। बैच ने सॉलॉसिटर जनरल तुषार मेता से जाच की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी। इसके जस्टिस सूखकांत ने कहा अगर अलाहबादिया को जल्दी ट्रैवल करने को पर्यावरण की तरफ होती है तो इसपर जाच प्रभावित होगी। जब जलरूप होते तो आप वहाँ नहीं होंगे। अलाहबादिया के बैकील ने कहा कि देश-विदेश की बड़ी पासपोर्टिंग का इंटरव्यू करना ही उनकी आजीविका है। इस पर जरिस सूखकांत ने कहा कि उम्मीद है जांच दो हफ्ते में पूरी कर लेंगे। इसलिए अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

## येशु-येशु वाले बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद

मोहाली (एजेंसी)। येशु-येशु वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने मंगलवार को 7 साल पुराने रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा से बचने के लिए पादरी बजिंदर कोर्ट में गिडिङ्गाने लगा- मेरे बच्चे छोटे हैं। पती बीमार है। मैं सोशल अडमी हूँ। मेरी टांग में रॉड डली हुई है, मुझ पर रहम किया जाए। मार कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया। बजिंदर को कोर्ट ने 3 दिन पहले दोषी करार दिया था। इसके बाद उसे पर्टियाला जेल भेज दिया गया था। बजिंदर पर आरोप हुई कि वह विदेश में बसने का लालच देकर महिला को अपने घर ले गया। वहाँ उसका रेप करके बिडियो बनाया। उसे धमकी भी दी कि आप विरोध किया तो बीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देंगा। गिडिंग के बैकील ने बताया कि बजिंदर अंतिम सास तक जेल में रहेगा।

## रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्योत्तिलक

नई दिल्ली (एजेंसी)। अप्रैल 2025 की शुरुआत हो गई है। 6 अप्रैल को रामनवमी और 14 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाएगी। रामनवमी के पौरोंके पर अयोध्या में रामलला का सूर्योत्तिलक होगा। इधर, 19 अप्रैल को पीएम मोदी की पहली जम्मू-श्रीनगर वार्दे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। आईपीएल का रोमांच चरम पर होगा। महोनेभर में 36 मैच खेल जाएंगे। वहाँ, ईंडियन नेवी एस्पी सी, जेईई मेन्स सेशन 2, कॉन्टेनर के कोर्ट में होगा। इनके अलावा, राजकुमार राव की मूर्खी भूल चूक माफ 10 अप्रैल को रिटायर होगी। डिनालूल ट्रूप दुनियाभर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाएंगे।

## वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में आज 12 बजे पेश होगा

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। एनडीए को बहस में बोलने के लिए 4 घंटे मिनट का समय मिला है। बाकी के बक्फ विषय के नेता वोले में पैश किया जाएगा। हालांकि, विषय ने बोलने के बाद पास किया जाएगा।

हालांकि, विषय ने बीएसी की बैठक से बॉक्साइट कर दिया। कांग्रेस ने जब इसके बाद सांसद गोरक्षण को अपने घोषणे और विषयको सदस्यों की बात नहीं सुनने का अरोप लगाया। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद बिल



ने अपने सांसदों के लिए विषय जारी किया। संसदीय कार्यमंत्री बोले- देश जानना चाहता है कि किसका क्या स्टेंड भाजपा ने विषय कर अपने सांसदों के सदन में पूरे समय मौजूद रहने को कहा है। वहाँ, कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को बजट सत्र के बाकी बचे तीनों दिन सदन में मौजूद रहने के लिए विषय जारी किया है। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम बिल पर चर्चा चारों हैं। सभी राजनीतिक दलों ने इस पर बोलने का अधिकार है। देश भी जानना चाहता है कि किस पार्टी का विषय के नाम पर चर्चा की जाएगी।



